



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 258]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16, 1999/कार्तिक 25, 1921

No. 258]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 1999/KARTIKA 25, 1921

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 39 (आर ई-99)/1997—2002

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1999

फा. सं. 01/92/180/320/ए एम-99-ई डी आई.—इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय ने एक परियोजना शुरू की है जिससे आयातक/निर्यातक इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने आवेदन दाखिल कर सकेंगे। इससे आयातकों/निर्यातकों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने लाइसेंस और अन्य आवेदनों की स्थिति जानने में मदद मिलेगी। शुरुआत में, विदेश व्यापार महानिदेशालय और सीमाशुल्क कार्यालय के बीच सम्पर्क से दोनों संगठनों के बीच सूचना का आदान-प्रदान करने में आसानी होगी जिससे समय की काफी बचत होगी। चूंकि शिपिंग बिल के साथ-साथ डी ई सी पुस्तिका में भी इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रविष्टियां की जाएंगी। ई डी आई की अन्य एजेंसियों (जैसे बैंक और पत्रन) जिनका निर्यातकों के साथ वास्तव पड़ता है, के साथ स्थापना की दिशा में पहला कदम होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर पहले कदम के तौर पर यह निर्णय लिया गया है कि सभी आयातकों/निर्यातकों कोडों का पूरा आंकड़ा आधार (डाटा बेस) स्थापित किया जाए।

सांविधिक आदेश संख्या 283(अ) दिनांक 31.3.97 के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खण्ड-3, उप खण्ड-2 में यथाअधिसूचित निर्यात और आयात नीति, 1997-2002 के पैराग्राफ -4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा, सभी क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों द्वारा अब तक जारी किए गए आयातक निर्यातक कोड नम्बरों के लिए प्रमाणपत्र में पहले से की गई प्रविष्टियों में परिवर्तन/अद्यतन करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1, संशोधित संस्करण-99, 1997-2002 में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित करते हैं

- विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट यानी एच टी टी पी:/डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.एन आई सी आई एन/एन्जिम पी ओ एल पर अपना होम पेज खोलना।
- आई ई सी आन लाइन संवर्धन/अद्यतन करने हेतु लिंक स्थापित करना।
- पहले से दी गई सूचना को ठीक/अद्यतन करना।
- वेबसाइट पर आवश्यक शुद्धियां करने के बाद संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जाच हेतु एक हार्ड कापी प्रेषित की जाएगी।
- सहायता, यदि आवश्यक हो, वैबसाइट पर भी उपलब्ध है।

6. प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 15.4(ख) के प्रावधान की छूट के तहत 31.12.99 से पहले की गई शुद्धि/संशोधन पर कोई जुर्माना देय नहीं होगा।
7. आवश्यक वृद्धि/अद्यतन करने के लिए सेवा प्रदान कर्ताओं की सेवाएं भी ली जा सकती हैं।

आयात और निर्यात के प्रेषण की निकासी उपर्युक्त प्रणाली के माध्यम से एकत्र की गई अद्यतन सूचना के आधार पर की जाएगी। यदि आयातक/निर्यातक द्वारा दी गई सूचना, वेबसाइट में उपलब्ध सूचना के साथ मेल नहीं खाती है तो सीमाशुल्क प्राधिकारी 1.1.2000 को या उसके बाद निकासी की अनुमति नहीं देगा।

अतः सभी निर्यातक/आयातक उस लाइसेंसिंग प्राधिकारी को वेबसाइट पर पूरी सूचना देगा और सभी निर्यातक/आयातक उस लाइसेंसिंग प्राधिकारी को वेबसाइट पर पूरी सूचना देगा और उसकी हार्ड कापी भी प्रस्तुत करेगा, जिसने आई ई सी नम्बर जारी किया था। वेबसाइट पर दी गई सूचना में कोई न होने की दशा में भी एक हार्ड कापी देनी होगी। सभी आई ई कोड धारकों को इस उद्देश्य के लिए बनाये गये कालम में पैन नम्बर (आयकर-स्पष्ट संख्या) का उल्लेख करना होगा। यह व्यवस्था अनिवार्य है। जिन्हें अब तक पैन नम्बर आवंटित नहीं किया गया है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उस संबंधित आयकर प्राधिकारी को आवेदन करें जो शीघ्रातिशीघ्र आई ई कोड धारकों को पैन नम्बर आवंटित करने के लिए सहमत हैं।

जिन मामलों में वेबसाइट पर सूचना अद्यतन कर ली गई है लेकिन उसकी हार्ड कापी प्रस्तुत नहीं की गई है तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी अद्यतन के बारे में कोई जांच नहीं करेगा। इसलिए वेबसाइट पर अद्यतन सूचना अनिवार्यतः एक हार्ड कापी के साथ दी जाए।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 39 (RE-99)/1997—2002

New Delhi, the 16th November, 1999

F. No. 01/92/180/320/AM '99/EDI.—With a view to taking steps towards E-commerce, the DGFT office has launched a project for enabling the Importers/Exporters to file their applications electronically. This would help the Exporters/Importers in seeking status of their licence and other applications electronically. The connectivity between the DGFT and the Customs, to begin with, will facilitate exchange of information between the two organisations and will lead to substantial saving of time as logging of DEEC book will also take place electronically along with the Shipping Bill. This would be a forerunner to the establishment of EDI with other agencies (like Banks and Ports) which have an interface with the exporters. As a first step towards achieving this goal, it has been decided to set up a complete data base of IE codes issued in favour of all the Importers/Exporters.

In exercise of powers conferred under paragraph 4.11 of the Export and Import Policy, 1997-2002, as notified in the Gazette of India extraordinary, Part-II- Section 3 – Sub- section (ii) vide S.O No. 283(E) dated 31.3.97, the Director General of Foreign Trade hereby lays down the following procedure in the Handbook of Procedures (Vol.1) (RE-99), 1997-2002 for changing/updating the entries already made in the certificate for IEC code numbers issued so far by all the Regional/Zonal offices.

1. Open the home page at DGFT web site viz. <http://www.nic.in/eximpol>.
2. Link IEC online addition/updation
3. Rectify/update the information already given.
4. After making necessary corrections on the website, a hard copy would be sent to the concerned licensing authority for post verification.
5. Help, if required, is also available on the website itself.
6. No penalty is payable if the correction/amendment is made before 31.12.99 in relaxation of the provision of paragraph 15.4(b) of the Handbook (Vol.1).
7. Help of service provider can also be taken for carrying out necessary addition/updation.

The consignments of imports and exports shall be cleared on the basis of the updated information collected through the above mechanism. In case the information furnished by the importer/ exporter does not match with the information available on the website, the Customs may not allow clearance on or after 1.1.2000.

All Exporters/Importers will therefore furnish the complete information on the website followed by a hard copy to be submitted to the licensing authority which had issued the IEC number. A hard copy will have to be furnished even if the information on the website does not require a change. All IE Code holders will have to mention the PAN (Income Tax distinctive number) in the column provided for this purpose. This is a mandatory provision. Those who have not yet been allotted PAN are advised to apply to the concerned Income Tax authorities who have agreed to allot PAN to IE Code holders expeditiously.

In such cases where the information has been updated in the website but hard copy is not furnished, no verification of updation shall be carried out by the licensing authority. Therefore, the updated information on the website has to be invariably followed with a hard copy.

This issues in public interest.

N.L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade